

RBI की 50वीं मौद्रिक नीति समिति की बैठक

प्रलिस के लयि:

भारतीय रजिख बैंक, मौद्रिक नीति समिति, लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, रेपो दर, कृत्रमि बुद्धमिता, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, डिजिटल लेंडिंग ऐप्स, युनफाइड पेमेंट्स इंटरफेस

मेन्स के लयि:

मौद्रिक नीति समिति के नरिणय, भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों का संग्रहण, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

भारतीय रजिख बैंक की 50वीं मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में ब्याज दरों और आर्थिक नीतियों पर उल्लेखनीय अपडेट सामने आई है।

- इस बैठक में लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT) अवसंरचना के आठ वर्षों पर प्रकाश डाला गया तथा मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने और आर्थिक दक्षता को बढ़ाने के उपायों को प्रस्तुत किया गया।

50वीं MPC बैठक के मुख्य तथ्य क्या हैं?

- MPC के दर नरिणय:**
 - MPC ने नीतिगत रेपो दर को 6.50% पर अपरविरतित रखने का नरिणय लिया। यह नरिणय मुद्रास्फीति के प्रबंधन और आर्थिक विकास का समर्थन करने हेतु समिति के वर्तमान दृष्टिकोण को दर्शाता है।
 - स्थायी जमा सुवधि (SDF) दर अपरविरतित रेपो दर के साथ संरेखित करते हुए 6.25% पर बनी हुई है।
 - सीमांत स्थायी सुवधि (MSF) दर और बैंक दर दोनों दरें 6.75% पर नरिधारित की गई हैं। इन दरों का उपयोग अर्थव्यवस्था के भीतर तरलता और उधार लेने की लागत का प्रबंधन करने के लिये किया जाता है।
 - MPC का प्राथमिक लक्ष्य मुद्रास्फीति को 4.0% के लक्ष्य के करीब लाने के लिये धीरे-धीरे समायोजन को समाप्त करना है। मजबूत आर्थिक विकास के बावजूद समिति आर्थिक वसितार का समर्थन करते हुए मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की आवश्यकता पर जोर देती है।
- विकास का आकलन:**
 - वैश्विक आर्थिक स्थिति: MPC ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर लेकिन असमान वृद्धि दर्शा रही है। वनरिमाण क्षेत्र में मंदी का अनुभव हो रहा है जबकि सेवा उद्योग का प्रदर्शन अच्छा बना हुआ है।
 - प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति की दर में धीरे-धीरे कमी देखी जा रही है, हालांकि सेवाओं की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं।
 - वभिन्न देश अलग-अलग मौद्रिक नीतियों अपना रहे हैं, कुछ केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती कर रहे हैं जबकि अन्य अपनी नीतियों को सख्त कर रहे हैं।
 - चुनौतियाँ: प्रमुख वैश्विक चुनौतियों में जनसांख्यिकीय बदलाव, जलवायु परिवर्तन, भू-राजनीतिक तनाव, बढ़ता सार्वजनिक ऋण और कृत्रमि बुद्धमिता जैसी प्रौद्योगिकी में प्रगति शामिल हैं। ये कारक मध्यम अवधि के वैश्विक विकास परदृश्य में अनश्चितताओं में योगदान करते हैं।
 - घरेलू आर्थिक स्थिति: MPC ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत की आर्थिक गतिविधि स्थिर मानसून प्रगति, उच्च खरीफ बुवाई और बेहतर जलाशय स्तर से प्रेरित सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ लचीली बनी हुई है।
 - वनरिमाण और सेवा क्षेत्र मजबूत हैं तथा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में तीव्र वृद्धि देखी जा रही है।
 - ग्रामीण मांग में वृद्धि और शहरी वविकाधीन व्यय में स्थिरता से घरेलू उपभोग को समर्थन मिल रहा है।
- मुद्रास्फीति के रुझान और नहितारथ:**
 - जून 2024 में हेडलाइन मुद्रास्फीति बढ़कर 5.1% हो गई, जिसका मुख्य कारण खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ना है। ईंधन की कीमतों

में गरिबों के साथ कोर मुद्रास्फीति (खाद्य और ईंधन की कीमतों को छोड़कर) में कमी आई।

- **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)** बास्केट में खाद्य पदार्थों का महत्वपूर्ण भार (लगभग 46%) होने के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों का समग्र मुद्रास्फीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। खाद्य पदार्थों, विशेषकर सब्जियों की उच्च कीमतों ने मुख्य मुद्रास्फीति को बढ़ा दिया है।
- **भावी दृष्टिकोण:** यद्यपि अलपावधि में खाद्य मुद्रास्फीति उच्च बनी रहने की उम्मीद है, फरि भी अनुकूल आधार प्रभाव और बेहतर मानसून की स्थिति के कारण कुछ राहत मिल सकती है।
- **वित्तीय बाजार की स्थितियाँ:**
 - MPC ने कहा कि आर्थिक मंदी, भू-राजनीतिक तनाव और कैरी ट्रेड गतिशीलता में बदलाव की चिंताओं के कारण वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता का अनुभव हुआ है।
 - इसके बावजूद, भारत के वित्तीय बाजार मजबूत समष्टि आर्थिक बुनियादी अवसंरचना के समर्थन से स्थिर हैं।
- **अतिरिक्त उपाय:**
 - **डिजिटल ऋण ऐप्स रपॉजिटरी:**
 - RBI बैंकों जैसी वनियमि संस्थाओं (RE) द्वारा उपयोग किये जाने वाले **डिजिटल लेंडिंग ऐप्स (DLA)** का एक सार्वजनिक संग्रह स्थापित करेगा। इस उपाय का उद्देश्य उपभोक्ताओं को **अनधिकृत डिजिटल ऋण** की पहचान करने में सहायता करना और डिजिटल लेंडिंग पारस्थितिकी तंत्र में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
 - यह घटनाक्रम RBI के डिजिटल ऋण पर सितंबर 2022 के दिशानिर्देशों के बाद आया है, जो **RBI वर्कगि गुरुप** की एक रपॉर्ट से प्रेरित है, जिसमें खुलासा किया गया है कि भारतीय एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं के लिये **उपलब्ध 1,100 डिजिटल लेंडिंग ऐप्स में से लगभग 600 अवैध हैं।**
 - **अनियमि डिजिटल ऋण के कारण उपभोक्ताओं का शोषण बढ़ रहा है,** जिससे इस तेज़ी से वकिसति हो रहे क्षेत्र में कड़े नियमन और उपभोक्ता सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता उजागर होती है।
 - RBI ने वनियमि संस्थाओं से यह सुनिश्चित करने को कहा कि **उधार सेवा प्रदाता (LSP)** और DLA दिशा-निर्देशों का पालन करें। उन्हें ब्याज दरों का खुलासा पहले ही कर देना चाहिये, उधारकर्ताओं को उत्पाद विवरण की जानकारी देनी चाहिये तथा जमिंदार ऋण देने को बढ़ावा देने हेतु उधारकर्ताओं की आर्थिक प्रोफाइल को कैचर करना चाहिये।
 - **यूपीआई लेनदेन सीमा:**
 - **यूनफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)** के माध्यम से कर भुगतान के लिये लेनदेन की सीमा **1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए** की जाएगी। यह समायोजन उपभोक्ताओं के लिये आसान और अधिक कुशल कर भुगतान की सुविधा हेतु बनाया गया है।
 - इस संशोधन का **लक्ष्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर भुगतान के उच्च मूल्य और आवृत्ति को त्वरित और सुविधाजनक बनाना है।**
 - RBI यूपीआई के माध्यम से 'प्रत्यायोजित भुगतान' शुरू करने की भी योजना बना रहा है, जिससे **द्वितीयक उपयोगकर्ता (जैसे पत्नी या पत्नी)** प्रथमिक उपयोगकर्ता के बैंक खाते का उपयोग करके भुगतान कर सकेंगे।
 - प्रथमिक यूपीआई उपयोगकर्ता अपने खातों पर द्वितीयक उपयोगकर्ताओं के लिये विशिष्ट भुगतान सीमाएँ निर्धारित करने में सक्षम होंगे।
 - इस सुविधा से डिजिटल भुगतान की पहुँच का वसितार होने और यूपीआई के 424 मिलियन व्यक्तियों के बढ़ते उपयोगकर्ता आधार को पूरा करने की उम्मीद है।
 - **नरितर चेक समाशोधन:**
 - आरबीआई ने भुगतान में तेज़ी लाने और दक्षता बढ़ाने हेतु दो कार्य दिसों के वर्तमान समाशोधन चक्र के बजाय **'ऑन-रयिलाइजेशन-सेटलमेंट' चेक ट्रंक्शन सिस्टम के साथ चेक के नरितर समाशोधन** का प्रस्ताव दिया है।
 - इस प्रणाली का उद्देश्य **प्रस्तुत के दिने कुछ घंटों के भीतर चेक का समाशोधन करना,** दक्षता में सुधार करना, नपिटान जोखिम को कम करना और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाना है।

लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचा

- फरवरी 2015 में शुरू किये गए, FIT का उद्देश्य आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिये अस्थायी वचिलन की अनुमति देते हुए **4% (±2%) के लक्ष्य के साथ मुद्रास्फीति को नरितरित करना है।**
- **RBI और वित्त मंत्रालय (GoI)** के बीच एक समझौते के माध्यम से स्थापित इस ढाँचे का उद्देश्य विकास को समायोजित करते हुए मुद्रास्फीति का प्रबंधन करना है। यह ढाँचा **उरजति पटेल समिति की रपॉर्ट (UPCR)** की सिफारिशों पर आधारित है।
- FIT का उद्देश्य मुद्रास्फीति को स्थिर करना है, जो **व्यापक आर्थिक स्थिरता को बढ़ा कर विकास को बढ़ावा दे सकता है।**
- RBI अधिनियम, 1934 को मौद्रिक नीति ढाँचे के लिये वैधानिक आधार प्रदान करने हेतु वर्ष 2016 में संशोधित किया गया था। **संशोधन में प्रत्येक पाँच वर्ष में एक बार RBI के परामर्श से सरकार द्वारा मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने का प्रावधान है।**
- इस ढाँचे को **मौद्रिक नीति को अधिक पारदर्शी और पूर्वानुमानित बनाने हेतु डिज़ाइन किया गया है,** जो RBI और सरकार के बीच समन्वय को मजबूत कर सकता है।

मौद्रिक नीति समिति

Monetary Policy Committee

मौद्रिक नीति समिति

- ★ **प्राधिकरण:**
 - ★ भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत मौद्रिक नीति के निर्माण हेतु अधिकृत है।
- ★ **उद्देश्य:**
 - ★ मूल्य स्थिरता और स्थिर विदेशी मुद्रा मूल्यों को सुनिश्चित करने के लिये मुद्रास्फीति या ब्याज दरों को समायोजित करना।

मौद्रिक नीति समिति (MPC)

- ★ **कानूनी ढाँचा:**
 - ★ संशोधित आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के तहत।
 - ❖ केंद्र सरकार को छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) का गठन करने का अधिकार है।
 - ★ MPC को वर्ष में कम-से-कम चार बार बैठक करनी होती है। MPC के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है, और वोटों की समानता की स्थिति में गवर्नर के पास दूसरा या निर्णायक वोट होता है।

संघटन

- ★ आरबीआई गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में।
- ★ मौद्रिक नीति के प्रभारी उप गवर्नर।
- ★ केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित किया जाने वाला बैंक का एक अधिकारी।
- ★ केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले तीन व्यक्ति।

कार्य

- ★ मौद्रिक नीति समिति रेपो दर निर्धारित करती है।
 - ❖ यह वह दर है, जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को प्रतिभूतियाँ खरीदकर उधार देता है।
 - ❖ यह अर्थव्यवस्था में अन्य सभी ब्याज दरों के लिये एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करती है।
- ★ हर छह महीने में एक बार RBI को मुद्रास्फीति के स्रोतों और 6-18 महीनों की अवधि के लिये मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान की व्याख्या करने हेतु 'मौद्रिक नीति रिपोर्ट' नामक एक दस्तावेज प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है।

DRISHTI IAS

DRISHTI IAS. DRISHTI IAS DRISHTI IAS DRISHTI IAS DRISHTI IAS DRISHTI IAS DRISHTI IAS DRISHTI IAS DRISHTI IAS DRISHTI IAS DRISHTI IAS DRISHTI IAS DRISHTI IAS

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

DRISHTI IAS

प्रश्न. मौद्रिक नीति समिति (MPC) के संबंध में नमिनलखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2017)

- यह आरबीआई की बेंचमार्क ब्याज दरों को तय करती है।
2. यह आरबीआई के गवर्नर सहित 12 सदस्यीय निकाय है जिसका प्रत्येक वर्ष पुनर्गठन किया जाता है।
3. यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है।

नमिनलखिति कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये :

- (a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 3
(d) केवल 2 और 3

उत्तर: (a)

प्रश्न. यदि भारतीय रिज़र्व बैंक एक वस्तुवादी मौद्रिक नीति अपनाने का निर्णय लेता है, तो वह नमिनलखिति में से क्या नहीं करेगा? (2020)

1. वैधानिक तरलता अनुपात में कटौती और अनुकूलन
2. सीमांत स्थायी सुवर्धा दर में बढ़ोतरी
3. बैंक रेट और रेपो रेट में कटौती

नमिनलखिति कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न: क्या आप इस बात से सहमत हैं कि स्थिर जीडीपी वृद्धि और कम मुद्रास्फीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अच्छी स्थिति में रखा है? अपने तर्कों के समर्थन में कारण बताइये। (2019)